[2012] 2 एस. सी. आर 856

तकनीक के लिए राष्ट्रीय परिषद। ईडीयू। &एएनआर।

वी.

वैष्णव संस्थान। तकनीक का। &एमजीटी।

(2012 की सिविल अपील संख्या 3505)

12 अप्रैल, 2012

[आर. एम. लोधा और एच. एल. गोखले, जे. जे.]

लागतों के बारे में

भारत का उच्चतम न्यालय

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र

सिविल अपील सं। 3505 2012

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा एवं अन्य

बनाम

वैष्णव तकनीकी &एमजीटी संस्थान। का।।

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश पीठ ग्वालियर में का न्यायालय डब्ल्यू. पी. संख्या 2010 के 4501 में के 20.09.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

साथ

सी. ए. सं. 3518 , 3519 , 3520 , 3521 , 3522 , 3523 , 3524 , 3525 , 3526 , 3506 , 3507 , 3508 , 3509 , 3510 , 3511 , 3512 , 3513 , 3514 , 3515 , 3516 और 3517 2012 का।

पल्लव शिशोदिया, सुनील सिंह परिहार, एस. के. सभरवाल, अमितेश कुमार, रविकांत, प्रीति कुमारी, नवीन प्रकाश, विवेक सिंह, संजय शरावत, मिलिंद कुमार, संजय घोष, नितिन भारद्वाज, अजीत कुमार गुप्ता, अजय कुमार भाटिया, जतिंदर कुमार भाटिया उपस्थित दलों के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एम. लोधा, जे.

1. विशेष अनुमति याचिकाएँ दाखिल करने में देरी को माफ किया गया।

2. अंतर्वर्ती आवेदन , 2011 की अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12815 की उत्तरदाता सं। 3 और 4 विशेष में दलों की श्रृंखला से हटाने की अनुमति के लिए अनुमति याचिकाकर्ता के जोखिम पर दी गई है।

3. अनुमति दे दी गई।

4. इन 22 अपीलों में से 9 दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होते हैं -

और 13 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से। 13 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों से उत्पन्न अपीलें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा की गई हैं। 9 अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय में विभिन्न संस्थानों द्वारा याचिका दायर की गई है।

5. इन अपीलों में, विचार के लिए सामान्य प्रश्न है। किया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 17 (1)। अधिनियम अधिनियम, 1993 ') के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा कार्यवाइ इस तरह के निरीक्षण मान्यता प्राप्त संस्थान की आवश्यक पाई जाती है, जहाँ एक कार्रवाई के खिलाफ विचार किया जाता ह , क्या ऐसी निरीक्षण 1993 के अधिनियम की धारा 13 के तहत आगे बढ़ना चाहिए या धारा 13 से स्वतंत्र, क्षेत्रीय समिति निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है?

6. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह राय ली है कि परिषद की ओर से यह अनिवार्य है कि वह 1993 के अधिनियम की धारा 13 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान को नोटिस

जारी करे और, यदि धारा 13 के तहत निरीक्षण पर, उल्लंघन पाए जाते हैं, फिर परिषद द्वारा संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थान को निरीक्षण के दौरान इसकी ओर इशारा करते हुए पर एक सूचना देने की आवश्यकता है मान्यता प्राप्त संस्थान ने निरीक्षण के दौरान इस प्रकार बताई गई कमियां कमियों हटाने में विफल रहता है, धारा 17 के तहत कार्रवाई हो सकती है है।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के विचार में, क्षेत्रीय समिति द्वारा निरीक्षण की 1993 की धारा 17 के तहत शक्ति के प्रयोग में निहित शक्ति है - 1993 के अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई करने से पहले 1993 के अधिनियम की धारा 13 के तहत नोटिस

परिषद की ओर से जारी करना अनिवार्य नहीं है

8. श्री अमितेश कुमार, एन. सी. टी. ई. के विद्वान वकील दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का दृढ़ता से बचाव किया। वह. 1993 के अधिनियम की धारा 13,14,15 और 17 को संदर्भित और प्रस्तुत किया कि धारा 13 के तहत निरीक्षण का प्रावधान है पूरी तरह से अलग है और क्षेत्रीय समिति द्वारा निरीक्षण की और मान्यता वापस और परिणाम 1993 के अधिनियम, नियम, विनियम आदि के प्रावधान उलंघन स्वयं हैं। परिषद द्वारा धारा 13 में प्रदत्त निरीक्षण के प्रावधान द्वारा निहित और सीमित नहीं । उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समिति धारा 17 के तहत उचित रूप से यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए, धारा 13 के प्रावधान को धारा 17 में पढ़ा जाता है, तो क्षेत्रीय समिति कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकती है

9. एन. सी. टी. ई. के विद्वान वकील ने भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णयों में दिए गए निर्देश की प्रकृति के बारे में शिकायत की ।

10. दूसरी ओर, संस्थानों के लिए विद्वान वकील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन किया। वे. प्रस्तुत किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का

दृष्टिकोण 1993 के अधिनियम के तहत वैधानिक योजना और इसके तहत बनाए गए नियम के अनुरूपता नहीं था ।

11. 1993 का अधिनियम संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना , के पूरे देश में लिए लागू किया गया था नियोजित और समन्वित शिक्षक शिक्षा प्रणाली का विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा देश, मानदंडों का विनियमन और उचित रखरखाव और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में और मानक मामलों के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह 1 जुलाई 1995 से लागू हुआ।

12. खंड 2 प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं से संबंधित है।

1993 अधिनियम में कहीं और। धारा 2 (सी) "परिषद"को इस प्रकार परिभाषित करती है -

इसके अंतर्गतः

"धारा 2 (ग) "परिषद्"से राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है -

धारा 3 "उप-धारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय परिषद् शिक्षक शिक्षा । धारा 2 (i) "मान्यता प्राप्त संस्थान"को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"धारा 2 (i) "मान्यता प्राप्त संस्था"का अर्थ है एक संस्था।

परिषद द्वारा धारा 14 के तहत मान्यता प्राप्त। धारा 2 (जे) "क्षेत्रीय समिति"को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"धारा 2 (जे) "क्षेत्रीय समिति"का अर्थ है एक समिति। धारा 20 के तहत स्थापित।

धारा 2 (के) के अनुसार, "विनियम"का अर्थ विनियम है। धारा 32 के तहत बनाया गया।

13. परिषद की स्थापना अनुभाग धारा 3 में प्रदान की गई है

. इसकी उप-धारा (2) के अनुसार, परिषद एक निकाय है जिसका स्थायी उत्तराधिकार है। उप-धारा (3) के तहत धारा 3, केंद्र के पूर्व अनुमोदन के साथ सरकार, परिषद अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थापित कर सकती है। जबकि परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

14. धारा 12 परिषद के कार्यों को निर्धारित करती है।

धारा 13, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः=

" 13. निरीक्षण।

(1) यह पता लगाने के लिए कि क्या मान्यता प्राप्त संस्थान इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसके अनुसार काम कर रहे हैं - ऐसी किसी संस्था का ऐसे व्यक्तियों द्वारा , ऐसे निदेशित व्यक्तियों द्वारा विहित तरीके से परिषद निरीक्षण कर सकती है।

(2) परिषद जिस तारीख को उप-धारा (1) के तहत निरीक्षण किया जाना है संस्था को सूचित करेगी ऐसी रीति से निरीक्षण के साथ जो विहित किया जाए कि - बनाया गया और संस्था संबद्ध होने का हकदार होगा

।

(3) परिषद उक्त संस्था ऐसे किसी भी निरीक्षण के परिणामों के संबंध में को सूचित करेगी, उस संस्था की राय का पता लगाने के बाद, उसके विचार और इस तरह के निरीक्षण का परिणाम पर उस संस्था को कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगी ।

(4) इस धारा के तहत संस्थान को सभी सूचना उसके कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि कोई कार्रवाई प्रस्तावित है तो उसे करने के लिए परिषद को रिपोर्ट करेगा , ऐसे किसी भी कार्य को लागू करने के उद्देश्यों के लिए अनुशंसा जैसा कि उप-धारा (3) में संदर्भित है।

15. शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता 1993 के अधिनियम के अध्याय IV में अभिनिर्धारित है । धारा 14,15,17 व 18, जो वर्तमान के विचार के लिए प्रासंगिक हैं।

निम्नानुसार पढ़िएः

" 14. शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता

। - (1) शिक्षक शिक्षा में पेशकश करने वाला प्रत्येक संस्थान या कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला संस्थान, नियत दिन या उसके बाद, मान्यता प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के तहत, क्षेत्रीय समिति को ऐसे रूप में और इस तरह से नियमों द्वारा निर्धारित एक आवेदन करेंगा

(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन के साथ भुगतान किया जाने वाला शुल्क

ऐसी होगी जो विहित , की जाए।

(3) क्षेत्रीय समिति द्वारा उप-धारा (1) के तहत किसी भी संस्थान से आवेदन प्राप्त होने पर , और उसके बाद संबंधित संस्थान से ऐसी अन्य चीज़ें प्राप्त करना जिन विवरणों को वह आवश्यक समझे, वे -

(क) यदि यह संतुष्ट है कि ऐसी संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, आवास, पुस्तकालय, योग्य कर्मचारी, प्रयोगशाला और यह कि यह ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करता है।

शिक्षक में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्था के उचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें

, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, इस तरह की मान्यता देने वाला आदेश पारित करे संस्था, ऐसी शर्तों के अधीन जो हो सकती हैं

(ख) यदि यह राय है कि ऐसी संस्था उपखंड (ए) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के से , ऐसी मान्यता से इनकार करने का आदेश पारित करें

बशर्ते कि इसके उपखंड (ख), तहत आदेश पारित करने से पहले क्षेत्रीय समित संबंधित संस्था को लिखित प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करें ।

(4) शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्थान किसी को मान्यता देने या अस्वीकार करने का उप-धारा (3) के तहत प्रत्येक आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उपयुक्त का्रवाही होने के लिए निकाय, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार और केंद्र सरकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

17. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और इसके परिणाम।

(1) जहाँ क्षेत्रीय समिति अपने प्रस्ताव पर या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर संतुष्ट है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ने किसी का इस अधिनियम के प्रावधानों, या नियमों, विनियमों, उसके अधीन किए गए आदेश या जारी किए गए आदेश, या कोई शर्त धारा 14 की उप-धारा (3) के तहत या धारा 15 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति थी, उल्लंघन किया है , यह ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था , लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिएः मान्यता को वापस ले सकता है ।

बशर्ते कि मान्यता संस्था, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिएः संस्थान को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए कोई उचित अवसर न मिले तब तक पारित नही किया जाएगा ।

पुन बशर्ते क्षेत्रीय समिति द्वारा पारित मान्यता से इनकार करना या कि वापस लेने का आदेश तिथि के बाद अगला शैक्षणिक सत्र के अंत से ही प्रभावी होगा

(2) क्षेत्रीय समिति द्वारा उप-धारा (1) के तहत पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति

-(क) मान्यता प्राप्त संस्थान को सूचित किया जाएगा और उसकी एक प्रति । संबंधित संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय जहा संस्था संबद्ध थी; जो संबद्धता रद्द करने के लिए भी भेजी जाएगी।

(ख) सामान्य जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) एक बार मान्यता प्राप्त संस्थान की मान्यता उप-धारा (1) के तहत वापस ली गई है ऐसी संस्था शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को बंद कर देंगी , और संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय उप-धारा (1) के तहत पारित आदेश के अनुसार संस्थान की संबद्धता को रद्द करेंगी जो उक्त आदेश का संचार की तारीख के बाद अगले शैक्षणिक सत्र का अंत से ्रप्रभावी होगी ।

(4) उप-धारा (1) के तहत मान्यता वापस लेना आदेश के लागू होने के बाद यदि कोई संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करता है , या जहां शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला संस्थान नियत दिन के तुरंत पहले इस अधिनियम के तहत मान्यता या अनुमति प्राप्त करना, विफल होने या उपेक्षा करने से , इसके अनुसार प्राप्त शिक्षक शिक्षा में योग्यता ऐसा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या कोई पाठ्यक्रम शुरू करने के बाद या । केंद्रीय के तहत रोजगार के उद्देश्यों के लिए योग्यता सरकार, कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय, या किसी भी क्षेत्र में द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक निकाय केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार ऐसे संस्थान में प्रशिक्षण को वैध नहीं माना जाएगा ।

18. अपील करते हैं। - (1) अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के तहत किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्त ऐसी निर्धारित अवधि के भीतर परिषद को अपील कर सकते हैं

(2) कोई अपील यदि इसके निर्धारित अवधि की समाप्तिः बाद लाइ जाती है तो इसे स्वीकार नहीं की जाएगी

बशर्ते कि यदि अपीलार्थी परिषद को संतुष्ट किया कि उसके पास पर्याप्त कारण निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं दाखिल करने का था, अपील बाद स्वीकार किया जा सकता है ।

(3) इस धारा के तहत की गई ऐसे प्रपत्र में और इसकी आदेश की एक प्रति व न्रिधारित शुल्क के साथ अपील की जाएगी।

(4) अपील के निपटारे की प्रक्रिया इस प्रकार होगी - जैसा कि निर्धारित किया जा सकता हैः बशर्ते कि अपील को अस्वीकार करने से पहले, अपीलार्थी को एक उचित अवसर दिया जाएगा , अपने मामले का प्रतिनिधित्व करें।

(5) परिषद अपील किए गए आदेश की पुष्टि या उसे उलट सकती है।

16. धारा 20 क्षेत्रीय समितियों से संबंधित है। उप- धारा (1) प्रावधान करैत अछि जे परिषद आधिकारिक राजपत्रमे अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रीय व्यवस्था स्थापित करत।

समितियाँ, अर्थात् (i) पूर्वी क्षेत्रीय समिति; (ii)

पश्चिमी क्षेत्रीय समिति; (iii) उत्तरी क्षेत्रीय समिति

समिति, और (iv) दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। इसका सरचना व सदस्यो की अवधि विभिन्न उप-अनुभाग मे दिया है । उप-धारा (6) में प्रावधान है कि - क्षेत्रीय समिति अपने धारा 14,15 और 17 कार्यों के अतिरिक्त परिषद द्वारा उसे सौंपा जाए निम्नलिखित कार्य करेगी -

ऐसे अन्य कार्य करती हैं, जो विनियम द्वारा निर्धारित किया जाए ।

17. परिषद को खंड 21 में प्रदत्त परिस्थितियों में क्षेत्रीय समिति समाप्त करने का अधिकार दिया गया है. धारा 27 परिषद को अपनी शक्तियां सौंपने और कार्य का अधिकार , धारा 32 की विनियमन बनाने शक्ति को छोड़कर, देती है।

18. धारा 31 केंद्र सरकार को नियम, जबकि धारा 32 परिषद को जबकि धारा 32 परिषद को विनिमय बनाने का अधिकार देती है ।

धारा 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नियम, 1997 (संक्षेप में, 1997 नियम ') शीर्षक से नियम बनाए हैं।

। हमारे विचार के उद्देश्यों के लिए नियम 8, जो निरीक्षण से संबंधित है प्रासंगिक नियम है

। नियम 8 निम्नानुसार प्रदान करता है -:

"8.निरीक्षणः

(1) परिषद मान्यता प्राप्त संस्थानों का उप-नियम (2) से (8) में निर्दिष्ट तरीका। से निरीक्षण कर सकती है।

(2) परिषद विशेषज्ञों के नामों के एक निरीक्षण दल के लिए विशेषज्ञों शिक्षक शिक्षा या शैक्षिक प्रशासन में जो मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करने में सक्षम हो का एक पैनल पैनल को मंजूरी देगी सभापति इनमें से कम से कम दो व्यक्तियों को नामित करेगा।

(3) परिषद अपने इरादे की सूचना देगी - प्रपत्र-'IV'में एक प्रश्नावली के साथ संस्थान को संस्थान से संबंधित सभी प्रासंगिक मामलों पर पंद्रह दिनों के भीतर जानकारी ।

(4) पूर्ण प्रश्नावली की प्राप्ति पर, परिषद निरीक्षण दल सदस्यों के नामों और संस्थान के निरीक्षण की तारीख का संचार करेगा ।

(5) जिस संस्थान का निरीक्षण किया जाना है वह संस्थान अपने एक अधिकारी या कर्मचारी को नामित करेगा , जो निरीक्षण टीम से जुड़े हों।

(6) निरीक्षण दल यह पता लगाएगा कि क्या संस्थान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है।

(7) निरीक्षण दल के सदस्य, यदि आवश्यक, समझते हैं, तो संकाय सदस्यों संस्थान के और अन्य कर्मचारी लोगों के साथ बातचीत करें ।
(8) निरीक्षण दल अपनी निरीक्षण "अंतिम दिन से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

19. उपरोक्त प्रावधानों के सर्वेक्षण से, यह देखा जा रहा कि परिषद की स्थापना शिक्षक शिक्षा के लिए नियोजित और समन्वित विकास; मानदंडों और मानकों के उचित रखरखाव के लिए शिक्षक शिक्षा और विविध कार्यों के निर्वहन के लिए 1993 के अधिनियम में इसे सौंपा गया सुनिश्चित करने के लिए की गई है । क्षेत्रीय समितियाँ हैं - वैधानिक रूप से प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त धारा 14,15 और 17 में और ऐसे अन्य कार्यों में भी जो रिपोर्ट करते हैं संस्थान, क्षेत्रीय समिति, की प्राप्ति पर निर्धारित आवेदन को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, विशेष रूप से यह संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी संस्था ने पर्याप्त वित्तीय संसाधन, आवास, पुस्तकालय, योग्य कर्मचारी, प्रयोगशाला और यह कि आवेदक-संस्थान अन्य कार्यों को पूरा करता है किसी पाठ्यक्रम के उचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें या शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण। यह केवल क्षेत्रीय समिति है एक संस्थान को मान्यता जारी करती है और वह है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित, के बाद परीक्षा निकाय ऐसी संस्था से संबद्धता प्रदान करती है ।

20. धारा 15 के तहत, क्षेत्रीय समिति है - जिस संस्थान को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है, उसे नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए अनुमति देने का अधिकार है।

21. धारा 17 क्षेत्रीय समिति को कारवाइ करने का अधिकार देती है , मान्यता प्राप्त संस्था के खिलाफ कार्रवाई जहां उसे किसी व्यक्ति से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है या वह स्वतः संतुष्ट है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ने 993 के अधिनियम या 1997 के नियमों, विनियमों, आदेशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है। या उसके तहत जारी किया गया, आदि अनुदान या मान्यता प्राप्त संस्थान ने मान्यता की शर्तों का उल्लंघन किया है।

22. एक बार किसी संस्थान के लिए क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है , परिषद को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक्ट 1993 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान कार्य करें। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिषद को मान्यता प्राप्त संस्थान का समय-समय पर निरीक्षण करवाना पड़ता है निरीक्षण के परिणामस्वरूप उसके द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाई किया जाता है को।

23. उपरोक्त वैधानिक योजना को देखते हुए, परिषद और वर्तमान के कानूनी विवादी दृष्टिकोण मानना कठिन है । यदि परिषद महसूस करती है कि उसका निरीक्षण का कार्य

धारा 13 के तहत क्षेत्रीय समितियाँ, करे उसे राष्ट्रीय परिषद द्वारा धारा 20 (6) या धारा 27 को लागू करके ऐसा किया जा सकता है।

24. 1993 के अधिनियम के प्रावधानों से जो स्पष्ट है वह है - उस मान्यता के बाद, एक संस्थान एक अलग स्थिति प्राप्त करता है। धारा 14 के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता और परीक्षा निकाय द्वारा संबद्धता दिए जाने पर, एक बाव मान्यता प्राप्त संस्थान काम करना शुरू कर देता है, जिसका हित शिक्षक, कर्मचारी और छात्र हस्तक्षेप करते हैं। इसके लिए यह सुनिश्चित करना कि मान्यता प्राप्त संस्थान 1993 के अधिनियम, 1997 के नियमों, विनियमों और ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थानों को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जाता है, निरीक्षण और उसके अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई का प्रावधान धारा 13 में बनाया गया है। धारा 13 द्वारा, के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान इसके अनुसार काम कर रहे हैं - 1993 के अधिनियम के प्रावधान या नहीं। उस उद्देश्य के लिए, यह सशक्त बनाता है परिषद ऐसे किसी भी संस्थान का निरीक्षण कराएगी ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया जो इसे निर्देशित कर सकते हैं, और इस तरह से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। परिषद क्षेत्रीय समिति को निरीक्षण के अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिकृत कर सकती है। लेकिन इस तरह यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसा मान्यता प्राप्त संस्थान 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, नियम 8 में निर्धारित निरीक्षण किया जाना चाहिए।

। 25. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 1997 के नियमों में, नियम 8 निरीक्षण से संबंधित है और उप-नियम (6) में प्रावधान है कि निरीक्षण दल यह पता लगाएगा कि क्या मान्यता प्राप्त संस्थान 1993 अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है।

26. 1993 के अधिनियम की धारा 13 की धारा (1) और (2) सह 1997 के नियमों के नियम 8 के अनुसार, में दिए गए अनुसार निरीक्षण पूरा होने पर परिषद को संबंधित संस्थान को अपने विचारों से अवगत कराना आवश्यक है। निरीक्षण के परिणाम के लिए और, यदि कमियां पाई जाती हैं, कमियों को पूरा करने के लिए ऐसी संस्था को सिफारिश करना। पूरा विचार यह है कि परिषद एक मूल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों पर नज़र रखती है। संस्थान को अपने कामकाज में अभाव पाया जाता है, इसे कमियों को सुधारने का अवसर एक दिया जाता है।

27. एक की मान्यता को रद्द करना या वापस लेना मान्यता प्राप्त संस्थान एक कठोर उपाय है। इसका परिणाम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को विस्थापित करना है। यही कारण है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कामकाज पर निरंतर निगरानी। निरीक्षण के बाद परिषद की सिफारिश पर, यदि कोई मान्यता प्राप्त संस्थान कमियों को ठीक नहीं करता है और जारी रखता है 1993 के अधिनियम के प्रावधानों नियम या विनियम, के उल्लंघन में कार्य या क्षेत्रीय समिति के धारा 17 तहत मान्यता को वापस लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी शक्ति है।

28. धारा 17 और 13 का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए।

धारा 17 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय समिति महसूस कर सकती है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का निरीक्षण आवश्यक है, इससे पहले कि वह संतुष्ट हो सके -

क्या ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था ने 1993 के अधिनियम या नियमों या विनियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन या इनमें से किसी का उल्लंघन किया है तब

धारा 13 के तहत पालन करना होगा। यदि क्षेत्रीय समिति को , परिषद द्वारा अपना कार्य निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है , क्षेत्रीय समिति निरीक्षण धारा 13 में दिए गए प्रावधानों और नियम 8 में निर्धारित किया गया है के अनुसार कर सकती है । जहाँ, हालांकि, क्षेत्रीय समिति महसूस करती है कि धारा 17 के तहत

प्रस्तावित कार्रवाई के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का निरीक्षण आवश्यक नहीं है । जाहिर है कि यह धारा 13 के तहत प्रदान किए गए निरीक्षण के मार्ग का पालन बिना कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

29. श्री अमितेश कुमार, एन. सी. टी. ई. के विद्वान वकील, प्रस्तुत किया कि धारा 17 के तहत एक कार्रवाई के लिए, अधिकांश में मान्यता प्राप्त संस्थान का निरीक्षण आवश्यक होंगे और, यदि धारा 13 के तहत निरीक्षण का मार्ग था इसके परिणामस्वरूप देरी होगी और धारा 17 के तहत पारित क्षेत्रीय समिति के आदेश के खिलाफ धारा 18 के तहत किसी पीड़ित संस्थान को दी गई अपील के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

प्रस्तुत करना हमें आकर्षित नहीं करता है। यह स्वीकार करना कठिन है कि यदि किसी का निरीक्षण किया जाए तो अनावश्यक देरी होगी। मान्यता प्राप्त संस्थान धारा 13 के संदर्भ में किया जाता है और जैसा कि नियम 8 में बताया गया है। बल्कि इस तरह से निरीक्षण

निष्पक्षता और निष्पक्षता लाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश इस तरह के निरीक्षण का शीघ्र समापन हमेशा किया जा सकता है परिषद द्वारा निर्मित। धारा 18 के तहत अपील के अधिकार की प्रभावशीलता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है निरीक्षण किया जाता है।

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

हमारी सराहना नहीं करता है और हम दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय को दरकिनार कर देते है । । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण जिस हद तक यह ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके विपरीत हैद अच्छा नही माना गया । दूसरे शब्दों में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कि धारा 17 के तहत कार्यवाही करने से पहले 1993 अधिनियम, धारा 13 में प्रदान किए गए निरीक्षण की प्रक्रिया है सभी स्थितियों में अनिवार्य रूप से पालन किया जाना अपास्त किया जाता है। अगर धारा 17 के तहत संतुष्टि एक मान्यता संस्थान, क्षेत्रीय समिति का निरीक्षण बिना प्राप्त किए जा सकती

है। धारा 13 के मार्ग का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जहां क्षेत्रीय समिति एक राय बनाती है कि इसके उचित के लिए इस बात का संतोष कि क्या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ने1993 के अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया या विनियम या उसके तहत बनाए गए या जारी किए गए आदेश या मान्यता की शर्तें, एक निरीक्षण आवश्यक है, तो अनिवार्य रूप से धारा 13 के तहत निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई का पालन करना होगा। हम उसी के अनुसार प्रश्न का उत्तर देते हैं।

31. ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित संस्थान वर्तमान में मान्यता वापस लेने के कारण कार्यात्मक नहीं है। जहाँ तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से उत्पन्न होने वाली अपीलें हैं संबंधित, एन. सी. टी. ई. द्वारा की गई अपीलों में, न्यायालय एक अंतरिम आदेश द्वारा मध्य प्रदेश के फैसले पर रोक लगा दी गई । जहाँ तक संस्थानों द्वारा दायर अपीलों का संबंध है

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से हम पाते हैं कि यह न्यायालय सूचित किया कि उन संस्थानों के संबंध में जिन्होंने अपील की है दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, क्षेत्रीय समिति ने पहले ही उनकी मान्यता वापस लेने का आदेश दे दिया था। लेकिन बाद में, मान्यता वापस लेने का आदेश दिया गया रिट याचिकाओं में निर्णय तक स्थगन का । यह होगा, इस प्रकार, देखा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने पर, संस्थान की मान्यता वापस लेने का आदेश सक्रिय हो गए हैं।

32. जिस पर हमने ऊपर चर्चा की है, उसमें हमारे विचार न्यायोचित होगा

यदि परिषद इनमें संबंधित सभी संस्थानों संस्थान संस्थान का , जो दिल्ली उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, को सम्पर्क किए है , का निरीक्षण करती है 1993 का अधिनियम धारा 13 के प्रावधान के अनुसार आज से छह सप्ताह के भीतर करेगी। परिषद

संबंधित संस्थानों को इसके परिणाम के बारे में सूचित करें । उन संस्थानों के संबंध में जहां निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाती हैं कमियों को यथाशिघ्र निरीक्षण के दौरान

कमियां पूरा करने का अवसर के बाद। उन संस्थानों के संबंध में जहां निरीक्षण के दौरान कमियां नहीं निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाती हैं या कमियों को पूरा करने वाले संस्थानों को जो उनके ध्यान में लाया गया निरीक्षण के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय समिति मान्यता रद्द करने के आदेश को वापस लेने का उचित आदेश जारी करेगी। में। उन संस्थानों का जो परिषद द्वारा दिए गए समय के भीतर कमियों को पूरा नहीं करते हैं क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता , वापस लेने का आदेश कायम रहेगी।

33. दीवानी अपीलों का बिना किसी लागतों के बारे में आदेश के उपरोक्त तरीके से निपटारा किया जाता है।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हो,

लम्बित न रहेंगी और निपटारा कर समझा जाएँ।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

के. टी.